अनदेखी

धनपुरी एसईसीएल सोहागपुर एरिया में स्थानीय युवाओं की अनदेखी पर बढ़ा विरोध, कोयला खदानों में बाहरी मजदूरों को प्राथमिकता देने के आरोप

स्थानीय युवाओं के रोजगार पर उठ रहे सवाल

▶ राजनीतिक आंदोलन कुछ दिनों में क्यों हो जाते हैं शांत? स्थानीय लोग उठा रहे सवाल

प्रदीप शर्मा

धनपुरी स्थित एसईसीएल सोहागपुर एरिया की कोयला खदानों में निजी कंपनियों द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर स्थानीय युवाओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र की अमलाई ओपन कास्ट, रामपुर ओपन कास्ट, शारदा ओपन कास्ट सहित कई भूमिगत खदानों में हजारों रोजगार के अवसर होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के आरोप लग रहे हैं। युवाओं का कहना है कि निजी कंपनियां स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे क्षेत्र में असंतोष और आक्रोश का माहौल बनता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर राजनीतिक दल विरोध और आंदोलन की बातें तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिस पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं।

नवभारत, धनपुरी। सोहागपुर एरिया लंबे समय से कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहां संचालित एसईसीएल की विभिन्न खदानों में प्रतिदिन भारी मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय में इन खदानों में कई निजी कंपनियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रही हैं। इन कंपनियों के पास मशीन संचालन, ट्रांसपोर्टिंग, ओवरबर्डन हटाने, सुरक्षा, तकनीकी कार्य और श्रमिकों से जुड़े हजारों रोजगार उपलब्ध हैं। इसके बावजूद स्थानीय युवाओं का आरोप है कि उन्हें रोजगार देने में लगातार अनदेखी की जा रही है। युवाओं का कहना है कि क्षेत्र के बेरोजगार लंबे समय से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन निजी कंपनियां बाहरी जिलों और राज्यों से लोगों को लाकर काम पर रख रही हैं। इससे स्थानीय लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है।

क्षेत्र के युवाओं का कहना है कि जिन गांवों और कस्बों की जमीनों पर खदानें संचालित हो रही हैं, वहां के परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई लोगों का आरोप है कि कंपनियां स्थानीय लोगों को यह कहकर टाल देती हैं कि उनके पास तकनीकी योग्यता या अनुभव नहीं है, जबकि बाहरी लोगों को आसानी से काम मिल जाता है। इससे युवाओं में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। अमलाई ओपन कास्ट, रामपुर ओपन कास्ट और शारदा ओपन कास्ट परियोजनाओं में बड़ी संख्या में निजी कंपनियां कार्य कर रही हैं। इन परियोजनाओं में भारी मशीनें, डंपर, ड्रिलिंग, लोडिंग और परिवहन जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि यदि कंपनियां चाहें तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कई बार रोजगार के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण युवाओं को जानकारी तक नहीं मिल पाती। यही कारण है कि क्षेत्र के बेरोजगारों में यह भावना लगातार मजबूत हो रही है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किए जाते रहे हैं। नेताओं द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। कई बार ज्ञापन सौंपे जाते हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। इससे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर यह मुद्दा हर बार अधूरा क्यों छोड़ दिया जाता है। युवाओं का कहना है कि यदि राजनीतिक दल वास्तव में गंभीर हैं तो उन्हें लगातार इस मुद्दे को उठाना चाहिए और कंपनियों पर दबाव बनाना चाहिए। केवल कुछ दिनों तक विरोध कर चुप हो जाना स्थानीय बेरोजगारों के हित में नहीं है। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। क्षेत्र के सामाजिक संगठनों और युवा समूहों ने भी अब इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यदि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में बड़ा जनआंदोलन खड़ा हो सकता है। कई युवाओं का कहना है कि खदानों से निकलने वाले कोयले से करोड़ों रुपये का कारोबार हो रहा है, लेकिन स्थानीय परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है बल्कि कंपनियों और स्थानीय समाज के बीच बेहतर संबंध भी बनते हैं। यदि स्थानीय लोगों की उपेक्षा होती है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर स्थानीय युवाओं के बढ़ते आक्रोश पर कब ध्यान दिया जाएगा। क्या निजी कंपनियों को स्थानीय रोजगार नीति के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा, या फिर यह मुद्दा भी केवल विरोध और आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल क्षेत्र के युवाओं की निगाहें प्रशासन, एसईसीएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हुई हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आपसी भाईचारे के साथ मनाई गई बकरीद

▶ मस्जिदों में अदा की गई नमाज, लोगों ने गले मिलकर दी मुबारकबाद

नवभारत , धनपुरी। धनपुरी नगर में आज बकरीद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही नगर की मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने नए कपड़े पहनकर अल्लाह की इबादत की और अमन-चैन तथा खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे नगर में भाईचारे और सौहार्द का वातावरण दिखाई दिया। सुबह फज्र की नमाज के बाद से ही मस्जिदों में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। निर्धारित समय पर ईद-उल-अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। मौलाना और इमामों ने अपने संदेश में लोगों को त्याग, बलिदान और इंसानियत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि बकरीद केवल कुर्बानी का त्योहार नहीं बल्कि यह एक-दूसरे की मदद करने, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने और समाज में प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है।

नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाकर और गले लगकर ईद की बधाई दी। बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। छोटे बच्चों ने नए कपड़े पहनकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और दोस्तों के साथ खुशियां मनाईं। नगर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने अपने घरों पर मेहमानों का स्वागत किया तथा सेवइयां और अन्य पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। बकरीद के अवसर पर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। नगर के प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल सुबह से ही तैनात रहा ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने मिली

प्रशासनिक अधिकारियों ने भी नगरवासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए शांति और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। धनपुरी नगर में हिंदू-मुस्लिम एकता की भी सुंदर मिसाल देखने को मिली। कई स्थानों पर अन्य समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी और उनके घर पहुंचकर खुशियों में शामिल हुए। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं दीं। पूरे दिन नगर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। बाजारों में भी रौनक देखने को मिली और लोग खरीदारी करते नजर आए। बच्चों ने मेले और दुकानों का आनंद लिया। कुल मिलाकर धनपुरी नगर में बकरीद का त्योहार प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के संदेश के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

श्रम प्रहरी बन अपंजीकृत संस्थानों की दे जानकारी

नवभारत, शहडोल । सहायक श्रम आयुक्त शहडोल ने जानकारी दी है कि कारखाना अधिनियम 1948 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशाएं एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। श्रमिकों के हितों के संरक्षण एवं उनको कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक है, कि सभी संस्थानों एवं निर्माण स्थलों का पंजीयन श्रम विभाग अंतर्गत अनिवार्य रूप से हो।

कारखाना अधिनियम 1948 यह प्रावधानित करता है, कि ऐसा कोई भी परिसर जहां 20 या अधिक श्रमिक विद्युत शक्ति के साथ अथवा या 40 से अधिक श्रमिक बिना विद्युत शक्ति के विनिर्माण कार्य में नियोजित है, उसे मुख्य कारखाना निरीक्षक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत नियोजक का यह दायित्व है, कि वह निर्माण कार्य प्रारभ करने से पूर्व निर्माण कार्य की सूचना अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध कराए उन्होंने कहा कि पंजीकरण न होने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। नियोजको का यह दायित्व ऐसी स्थिति में श्रमिक कल्याण हेतु है, कि समस्त संस्थाओं का पंजीयन किया जाए।

पंजीयन नहीं होने की स्थिति में होगी दंडात्मक कार्यवाही

कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीयन नहीं होने की स्थिति में नियोजक को अधिकतम 1 लाख का जुर्माना एवं था 2 वर्ष तक की कारवास या दोनों की कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार निर्माण स्थलों का पंजीयन नहीं कराए जाने पर 2 हजार रूपए का जुर्माना या 3 माह तक कारावास या दोनों की कार्यवाही की जा सकती है इस प्रकार, दंडात्मक कार्यवाही से बचाने के लिए सभी नियोजक अपनी संस्था एवं निर्माण कार्य का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। श्रम प्रहरी के रूप में अब आमजन भी दे सकेंगे अपंजीकृत संस्थानों की सूचना ।

भाजपा के झंडे तले छलक रहा शराब का साम्राज्य !

▶ सुशासन के दावों पर मदिरा का तमाचा, भाजपा नेता ही बने शराब सिंडिकेट के कथित सरगना!

नवभारत , धनपुरी। धनपुरी, बुढ़ार व कोयलांचल छेत्र में इन दिनों शराब कारोबार ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि अब यह केवल अवैध कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में पलता खुला सिंडिकेट दिखाई देने लगा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कंधों पर समाज और नैतिकता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हीं कंधों पर अब शराब माफिया फलता-फूलता नजर आ रहा है। आरोप सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं पर लग रहे हैं, जिनमें राजू, बबलू, वीरेंद्र और अमरेश जैसे नाम चर्चा के केंद्र में हैं।

शहर से लेकर गांव तक शराब का जाल इस कदर फैल चुका है कि मानो जिले में विकास नहीं, बल्कि 'मदिरा मिशन' चलाया जा रहा हो। हालत यह है कि शराब दुकानों के कर्मचारी और कथित गुर्गे आम लोगों से मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शराब दुकानें अब व्यापारिक केंद्र कम और गुंडागर्दी के अड्डे ज्यादा बन चुकी हैं। बहस से शुरू होने वाले विवाद खुले झगड़े में बदल रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। सूत्र बताते हैं कि नए ठेके लागू होने के बाद जिले में एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय हुआ, जिसने शराब कारोबार को 'राजनीतिक संरक्षण' के दम पर बेलगाम बना दिया। आरोप है कि भाजपा से जुड़े कुछ चेहरे इस पूरे खेल में कथित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिन नेताओं के पोस्टरों में भाजपा का झंडा और राष्ट्रवाद दिखाई देता है, उन्हीं पर अब शराब कारोबार को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं।

प्रिंट रेट की खुलेआम धज्जियां जनता की जेब पर डाका

जिले में शराब दुकानों पर खुलेआम ओवररेटिंग का खेल चल रहा है। उपभोक्ता नियमों को ताक पर रखकर शराब की बोतलों और बियर पर मनमानी कीमत वसूली जा रही है। जानकारी के मुताबिक 200 रुपये की बियर 240 रुपये तक बेची जा रही है, वहीं क्वार्टर और बोतलों पर भी 40 से 50 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ठेकेदारों द्वारा ऊंची बोली लगाकर लिए गए ठेकों का भार अब आम जनता की जेब से वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, गांव-गांव तक शराब की पैकारी धड़ल्ले से पहुंचाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जिले में प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो चुका हो और शराब माफिया ही असली सरकार चला रहे हों। अमृतकाल के नाम पर जनता को विकास नहीं, बल्कि शराब की 'होम डिलीवरी' मिल रही है।

धर्म और संस्कार की राजनीति करने वाले अब शराब कारोबार के चेहरे

सबसे बड़ा सवाल भाजपा की उस कथित नैतिक राजनीति पर खड़ा हो रहा है, जिसमें संस्कार, धर्म और सुशासन की बातें की जाती हैं। आरोपों के घेरे में आया 'बबलू' नामक शख्स भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ चुका है। यही नहीं, कुछ समय पहले धार्मिक नगरी अमरकंटक में शराब पहुंचाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। वायरल वीडियो और चर्चाओं में यह मामला जमकर उछला, लेकिन कार्रवाई आज तक शून्य रही। जनता पूछ रही है कि आखिर प्रशासन की चुप्पी का राज क्या है? क्या सत्ता और शराब का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका है कि कानून भी इनके सामने घुटने टेक चुका है। फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि जिले में शराब माफिया के दांतों में प्रशासन की उंगलियां फंसी हुई हैं और सत्ता संरक्षण के दम पर पूरा खेल बेखौफ जारी है।

भीषण गर्मी से बेहाल जनजीवन, दोपहर में सूने पड़े रहे बाजार

▶ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर छा रहा सन्नाटा, 43 डिग्री के पार पहुंच रहा तापमान

नवभारत,शहडोल। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने आमजन का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पिछले करीब 10 दिनों से दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि रात का तापमान भी 26 से 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सुबह 10 बजे के बाद बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

दोपहर के समय शहर के प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी का असर छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के समय ग्राहक लगभग नहीं के बराबर आ रहे हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है।

गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

गर्मी के साथ चल रही लू जैसी गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सिर और चेहरे को कपड़े से ढंककर निकल रहे हैं। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उल्टी, चक्कर, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी शिकायतें लेकर लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

विशेषज्ञों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। चिकित्सकों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी और धूप में लंबे समय तक रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है। शहरवासियों ने प्रशासन से प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर ठंडे पेयजल एवं छांव की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में लोगों की चिंता और बढ़ती नजर आ रही है।

इनका कहना है

तेज धूप और गर्मी से बचना जरूरी है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग दोपहर में बाहर न निकलें। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें।

डॉ. गंगेश टांडिया, चिकित्सक

दोपहर के समय बाजार पूरी तरह सूना हो जाता है। सुबह और शाम को ही ग्राहक आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है।

रामप्रसाद गुप्ता, दुकानदार

बच्चों को दिन में बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। घर में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। लगातार बिजली की जरूरत पड़ रही है।

सुनीता मिश्रा, गृहिणी

दोपहर में सड़क पर सवारी बहुत कम मिल रही है। गर्म हवा के कारण लगातार वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है।

राकेश यादव, ऑटो चालक

टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने हर्राटोला में कृषि मेला आयोजित

नवभारत, शहडोल। जिले में टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी की घटती उर्वरता को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड बुढार के ग्राम हर्राटोला में एक दिवसीय कृषि मेला सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक एवं हरी खाद आधारित खेती के लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जय सिंह मरावी ने कहा कि किसान परंपरागत एवं जैविक खेती की नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हरी खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफे का माध्यम बन सकती है। विधायक ने किसानों को ढैंचा और सनई जैसी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

वैज्ञानिकों ने बताई हरी खाद की उपयोगी तकनीक

संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बृजकिशोर प्रजापति ने हरी खाद के प्रयोग की वैज्ञानिक विधियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को ढैंचा, सनई और मूंग को हरी खाद के रूप में उपयोग करने की तकनीक समझाई। उन्होंने बताया कि हरी खाद के उपयोग से यूरिया एवं डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जिससे खेती की लागत घटती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। सहायक संचालक कृषि अनुराग पटेल ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए हरी खाद से मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ने, जलधारण क्षमता मजबूत होने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक वितरण एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी किसानों को दी।

बैठक

जय अंबे कंपनी समेत अन्य कंपनियों में स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज

रामपुर के किसानों और ग्रामीणों की हलचल के बाद हरकत में आया प्रबंधन, महाप्रबंधक बीके जेना ने की अहम बैठक

नवभारत, धनपुरी । एसईसीएल सोहागपुर एरिया के रामपुर ओपन कास्ट में पिछले कई दिनों से किसानों और ग्रामीणों के बीच चल रही हलचल और बढ़ते असंतोष को देखते हुए सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक बी.के. जेना स्वयं रामपुर पहुंचे और जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक कर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। लगभग दो घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में विस्थापन, पुनर्वास, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया और ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को लेकर बिंदुवार विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों को मजबूती से प्रशासन के सामने रखा।

जानकारी के अनुसार रामपुर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं और कंपनियों के विस्तार कार्यों के चलते ग्रामीणों के बीच लंबे समय से विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा बना हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनें प्रभावित हो रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक संतोषजनक पुनर्वास और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए हैं। इसी को लेकर क्षेत्र में लगातार चर्चा और विरोध की स्थिति बन रही थी। ग्रामीणों की इसी हलचल को गंभीरता से लेते हुए महाप्रबंधक बी.के. जेना ने रामपुर पहुंचकर सीधे संवाद करने का निर्णय लिया।

बैठक में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठा कि जिन ग्रामीणों की जमीनें परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई हैं, उन्हें नियमानुसार मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई प्रभावित परिवार आज भी रोजगार और पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों ने विशेष रूप से जय अंबे कंपनी एवं अन्य निजी कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन नियुक्तियों में स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए स्पष्ट कहा कि यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज हो सकता है। महाप्रबंधक बी.के. जेना ने बैठक में उपस्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मामलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही कंपनियों से चर्चा कर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। बैठक में महाप्रबंधक संचालन मनीष श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप शर्मा सहित विभागीय अधिकारी एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि प्रबंधन की मंशा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। ग्रामीणों की ओर से बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने विस्थापन और रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की जमीन ली जाती है तो उसके परिवार को स्थायी रोजगार और उचित पुनर्वास मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है और कंपनियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।पूर्व एसडीएम एवं वरिष्ठ नेता रमेश सिंह ने भी बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन और कंपनियों को संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद और पारदर्शिता से ही विवादों को रोका जा सकता है। यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में असंतोष बढ़ सकता है। बैठक में ग्राम पंचायत रामपुर के सरपंच, जनपद सदस्य एवं सभापति चंद्र कुमार तिवारी ने भी स्थानीय समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कंपनियों को सीएसआर मद के तहत क्षेत्र के विकास में भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। उप सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर, सदस्य जिला पंचायत श्रीमती शांति मनमोहन चौधरी, बिछिया के सरपंच, अतरिया के सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा जब भी भर्ती निकाली जाए तो उसमें स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे क्षेत्र की बेरोजगारी कम होगी और लोगों का विश्वास भी बना रहेगा। बैठक के दौरान कई ग्रामीणों ने व्यक्तिगत समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। कुछ लोगों ने मुआवजा भुगतान में देरी की शिकायत की तो कुछ ने पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को नोट करते हुए समाधान का भरोसा दिलाया।

बैठक के अंत में महाप्रबंधक बी.के. जेना ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच लगातार संवाद बनाए रखा जाएगा ताकि किसी भी समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। रामपुर में हुई यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय बाद प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचे और सीधे संवाद किया। इससे क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द निकल सकता है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई चाहिए। आने वाले दिनों में प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी रहेगी।